Eastern Railway
(Personnel Department)
17 N. S. Road, Kolkata - 700 001

Serial Circular No.133/2018

No. E.678/0/3/Vol.VII

Kolkata, Dated: 05/07/2018

All Concerned
(as per standard list)

Sub: Amendment to para 1004 and 1005 of IREM Volume I (1989edition) - Clarification in respect of claims not over three years old from the due date.

******

The instructions of Ministry of Railways (Railway Board) on the above subject issued vide letter No. E(G)2014/AL 1-20 dated 19/06/2018 (**RBE No. 80/2018**) along with Advance Correction Slip (ACS) No.**255** of Paras 1004 and 1005 of IREM, Vol.I (Revised Edition 1989) First Re-print Edition, 2009, are communicated herewith for information, guidance, and necessary action.

DA: As above.

05/7/18
(U. Lahiri)
Dy. Chief Personnel Officer/R
For Chief Personnel Officer
Phone No - 24103 (Rly.)
05/7/18

Index No. 1028: Amendment to Paras 1004 and 1005 of IREM, Vol.I (Revised Edition 1989) relating to sanction an investigation of arrears claims.

6 3/4

RBE No. 80 /2018

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

No. E (G)2014/AL 1- 20 New Delhi, Dated 19 .06.2018

The General Managers,
All Indian Railway & PU's
(As Per Standard Mailing List)

Sub: Amendment to para 1004 and 1005 of IREM Volume I (1989 edition) – clarification in respect of claims not over three years old from the due date.

In terms of paragraph 1004 of the IREM volume – I (1989 edition) General Managers are authorized to sanction an investigation of arrears claims : (i) when the claim is not over three years old from the date it becomes due, irrespective of the amount involved; (ii) when the claim is over three years old but the amount of the claim pertaining to the period beyond three years does not exceed Rs. 10,000/-. In terms of Para 1005 ibid, the cases where the amount of the claims for the period beyond three years exceeds Rs. 10,000/-, investigation of the portion within the three years limit is sanctioned by the General Manager and the balance (i.e. the portion beyond three years) is referred to Railway Board for orders.

It has come to the notice of Board that some confusion prevails on different Zonal Railways as regards interpretation of the phrase "from the date it becomes due" mentioned in Para 1004 of the IREM volume-I as referred to above. The matter has since been considered in Railway Board and it is observed that any arrear becomes due to an employee as a result of directions/orders of a Court/Tribunal etc. or pursuant to a decision taken by the competent authority upon a representation made by the concerned employee or his representative through the available means of grievance redressal etc. In the aforesaid background, Board has decided that the term/phrase "from the date it becomes due" mentioned in para 1004 of IREM shall be construed as:
"the date of administrative orders issued pursuant to the directions/orders of the Court. Tribunal etc. or the date of administrative orders issued pursuant to the decision of the competent authority on a representation received from the affected employee or his/her representative etc., as the case may be, leading to arising of arrears claim."

The period of three years mentioned in Para 1004 and 1005 of IREM shall be reckoned from the due date as clarified hereinabove.

Accordingly, the provision contained in paragraph 1004 and 1005 of IREM volume I (1989 edition) amended as per the Advance Correction Slip No.255.

This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

Please acknowledge receipt.

DA: As above

(Sanjay Gauri)
Joint Director Estt.(G)
Railway Board

contd... 2/-

Advance Correction Slip to the Indian Railway Establishment Manual (IREM) Volume-I (1989 edition)

Advance Correction Slip No. 255.
The following may be inserted below Para 1004 Clarification:- The date from which due shall be the date of administrative order issued pursuant to directions/orders of the Court, Tribunal etc. or the date of administrative orders issued pursuant to the decision of the competent authority on a representation received from the affected employee or his/her representative etc. as the case may be, leading to claim for payment of arrears.

(Authority-Railway Board's letter No. E(G)2014/AL 1-20 dated. .06.2018)

1431 26

0/ 03/7/18

29 JUN
1689

आर बी ई सं. 80 /2018

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

Central Registry / E. Rly
Date of Receipt
Serial No..6/29/6

सं. ई(जी)2014/एएल 1-20

नई दिल्ली, दिनांक 19 - 05-2018

महा प्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(मानक डाक सूची के अनुसार)

PCPO

विषयः **भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द I (1989 संस्करण) के पैरा 1004 और 1005 में संशोधन -उन दावों के संबंध में स्पष्टीकरण जो नियत तारीख से तीन वर्ष से अधिक पुराने न हो.**

भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द - I (1989 संस्करण) के पैरा 1004 के अनुसार महाप्रबंधक बकाया दावों की जांच की मंजूरी के लिए प्राधिकृत हैः (i) जब दावा नियत तारीख से तीन वर्ष से अधिक पुराना नही हो, इसमें शामिल राशि पर ध्यान दिए बिना; (ii) जब दावा तीन वर्ष से अधिक पुराना हो लेकिन तीन वर्ष से आगे की अवधि के संबंध में दावे की राशि 10,000/- से अधिक नहीं हो. पैरा 1005 के अनुसार, वे मामले जिनमें तीन वर्ष से आगे की अवधि के लिए दावों की राशि 10,000/- से अधिक हो, तीन वर्ष की सीमा के भीतर वाले भाग की जांच की मंजूरी महाप्रबंधक द्वारा दी जाती है एवं शेष (अर्थात् तीन वर्ष से आगे के भाग) भाग के लिए आदेशों के लिए रेलवे बोर्ड को भेजी जाएगी.

बोर्ड के ध्यान में आया है कि भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द - I के पैरा 1004 में उल्लिखित वाक्य "उस तारीख से जब से यह देय है" की व्याख्या के संबंध में भिन्न क्षेत्रीय रेलों में कुछ संदेह है जैसा ऊपर दिया गया है. अब इस मामले पर रेलवे बोर्ड में विचार किया गया है एवं यह देखा गया है कि कर्मचारी को कोई भी बकाया अदालत/अधिकरण आदि के निर्देशों/आदेशों के परिणामस्वरूप अथवा संबंधित कर्मचारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा शिकायत निवारण आदि के मौजूदा माध्यमों से किए गए अभ्यावेदन पर सक्षम प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार देय होता है. उक्त पृष्ठभूमि में, बोर्ड ने निर्णय लिया है कि भारतीय रेल स्थापना नियमावली के पैरा 1004 में उल्लिखित शब्द/वाक्य "उस तारीख से जब से यह देय है" को निम्नानुसार समझा जाएः

02 JUL 2018
DY. CPO (R)

...2/-

"अदालत, अधिकरण आदि के निर्देशों/आदेशों के अनुसार जारी किए गए प्रशासनिक आदेशों की तारीख अथवा प्रभावित कर्मचारी अथवा उसके प्रतिनिधि आदि से प्राप्त अभ्यावेदन पर सक्षम प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार जारी किए गए प्रशासनिक आदेशों की तारीख, जैसा भी मामला हो, से बकाया के दावे होंगे."

भारतीय रेल स्थापना नियमावली के पैरा 1004 और 1005 में उल्लिखित तीन वर्ष की अवधि की गणना नियत तारीख से की जाएगी जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है.

तदनुसार, भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द I (1989 संस्करण) के पैरा 1004 और 1005 में अंतर्विष्ट प्रावधान अग्रिम शुद्धि पर्ची सं....255...... के अनुसार संशोधित किया जाए.

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

कृपया पावती दें.

संलग्नः यथोक्त.

(संजय गौरी)
संयुक्त निदेशक स्थापना (सा.)
रेलवे बोर्ड

भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द I (1989 संस्करण) के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 255.

पैरा 1004 स्पष्टीकरण के नीचे निम्नलिखित को जोड़ा जाए:- वह तारीख जिससे देय होगा अदालत, अधिकरण आदि के निर्देशों/आदेशों के अनुसार जारी किए गए प्रशासनिक आदेशों की तारीख अथवा प्रभावित कर्मचारी अथवा उसके प्रतिनिधि आदि से प्राप्त अभ्यावेदन पर सक्षम प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार जारी किए गए प्रशासनिक आदेशों की तारीख होगी जैसा भी मामला हो, जिससे बकायों के भुगतान के दावे होंगे.

(प्राधिकार- रेलवे बोर्ड पत्र सं. ई(जी)2014/एएल 1-20 दिनांक 19.06.2018)